[2024] 5 एस.सी.आर. 596 : 2024 आई.एन.एस.सी. 446

तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

बनाम

तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन एम्प्लॉइज वेलफेयर यूनियन और एक अन्य

(2024 की दीवानी अपील संख्या 6511)

17 मई 2024

[संजय करोल और प्रसन्न भालचंद्र वराले, न्यायमूर्तिगण]

विचार के लिए मुद्दा

क्या तमिलनाडु औद्योगिक प्रतिष्ठान (कामगारों को स्थायी दर्जा प्रदान करना) अधिनियम, 1981 पक्षकारों पर लागू होगा; क्या निगम को तमिलनाडु दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के अनुसार औद्योगिक प्रतिष्ठान कहा जा सकता है; और क्या संघ (यूनियन) के सदस्य कामगार के रूप में अर्हता प्राप्त करेंगे और इस प्रकार, अधिनियम की धारा 3 के तहत स्थायी स्थिति के लिए पात्र होंगे; और क्या गैर-रोजगार पर सवाल उठाने वाले 'औद्योगिक विवाद दावा' को शुरू करने का सुझाव संधारणीय था, यह देखते हुए कि श्रम निरीक्षक ने पहले ही इस संबंध में आदेश पारित कर दिए थे।

निर्णय सार

तमिलनाडु औद्योगिक प्रतिष्ठान (कामगारों को स्थायी दर्जा प्रदान करना) अधिनियम, 1981 – धारा 2(3), 7 – तमिलनाडु दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1947 – धारा 2(3), 2(6) – सरकारी निगम के कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग की – श्रम निरीक्षक ने कामगारों को स्थायी दर्जा प्रदान किया – उच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा और कर्मचारियों को

रोजगार प्रदान करने का निर्देश दिया – प्रति-अपीलें – 1981 के अधिनियम की पक्षकारों पर प्रयोज्यता के संबंध में मुद्दा – क्या निगम को 1947 के अधिनियम के अनुसार एक औद्योगिक प्रतिष्ठान कहा जा सकता है – क्या संघ के सदस्य कामगार के रूप में अर्हता प्राप्त करेंगे और इस प्रकार अधिनियम की धारा 3 के तहत स्थायी स्थिति के लिए पात्र होंगे – प्रतिप्रेषण पर उच्च न्यायालय, क्या श्रम निरीक्षक के आदेश की अनदेखी कर सकता था और गैर-रोजगार पर सवाल उठाते हुए 'औद्योगिक विवाद दावा' शुरू करने का सुझाव दे सकता था:

अभिनिर्धारित: निगम द्वारा संचालित गतिविधियां 1947 के अधिनियम की धारा 2(3) के तहत उल्लिखित गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं – निर्माण कार्य, जिसे निगम, अपनी स्वयं की स्वीकृति से, करता है, गैर-सरकारी निकायों जैसे कि फर्मों, कंपनियों और व्यक्तियों के लिए भी है – 1981 के अधिनियम की धारा 7 की भाषा का तात्पर्य है कि यह अधिनियम उन कामगारों पर लागू नहीं होगा जो भवनों और इसी तरह के निर्माण या अन्य निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, चाहे वह संरचनात्मक, यांत्रिक या विद्युत हो और इस प्रकार, विशेष रूप से निर्माण कार्य में लगे प्रतिष्ठानों और उसके कामगारों को छूट दी जाएगी – हालाँकि, यह निगम को अधिनियम के तहत जिम्मेदारियों या दायित्वों से अपना पल्ला झाड़ने की अनुमति नहीं देगा, क्योंकि निगम द्वारा किया जाने वाला निर्माण, इसके द्वारा की जाने वाली कई गतिविधियों में से केवल एक है – सभी श्रमिकों को अधिनियम के दायरे से बाहर करना, विशेष रूप से, जब उक्त श्रमिक निर्माण कार्य करने वाले नहीं थे, अनुचित है – कर्मचारी द्वारा 24 महीनों के लिए 480 दिनों या उससे अधिक समय तक सेवा में निर्बाध रूप से बने रहने की शर्त पूरी होने पर, अधिनियम पक्षकारों पर लागू होगा – इसके अलावा, प्रतिप्रेषण का दायरा सीमित था – चूंकि उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अधिनियम लागू होगा, उसके पास श्रम निरीक्षक के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था – उसे केवल यह आदेश देना चाहिए था कि श्रम निरीक्षक का आदेश, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया

था कि संघ के सदस्यों को स्थायी रोजगार दिया जाए, का अनुपालन किया जाए। [कंडिका 21-25, 27, 28]

न्याय दृष्टान्त

कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी **[2006] 3 एस.सी.आर. 953 : (2006) 4 एस.सी.सी. 1;** *महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम कास्ट्राईब राज्य परिवहन कर्मचारी संगठन* **[2009] 13 एस.सी.आर. 937 : (2009) 8 एस.सी.सी. 556;** *यू.पी. पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और एक अन्य बनाम बिजली मजदूर संघ और अन्य* **[2007] 5 एस.सी.आर. 256 : (2007) 5 एस.सी.सी. 755;** *ओएनजीसी लिमिटेड बनाम पेट्रोलियम कोल लेबर यूनियन और अन्य* **[2015] 5 एस.सी.आर. 474 : (2015) 6 एस.सी.सी. 494;** *अजय पाल सिंह बनाम हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन* **(2015) 6 एस.सी.सी. 321;** *रणबीर सिंह बनाम एस.के. रॉय, अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम और एक अन्य* **[2022] 10 एस.सी.आर. 986 : (2022) एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 521 – संदर्भित किया गया।**

अधिनियमों की सूची

तमिलनाडु औद्योगिक प्रतिष्ठान (कामगारों को स्थायी दर्जा प्रदान करना) अधिनियम, 1981; कंपनी अधिनियम, 1956; तमिलनाडु दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1947; औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947।

मुख्य शब्दों की सूची

औद्योगिक विवाद दावा; श्रम निरीक्षक; औद्योगिक प्रतिष्ठान; संघ के सदस्य; कामगार; कामगारों को स्थायी दर्जा; नियमितीकरण; वाणिज्यिक तत्व; निर्माण कार्य; गैर-सरकारी निकाय; प्रतिप्रेषण का दायरा।

प्रकरण से उत्पन्न

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2024 की दीवानी अपील संख्या 6511

2001 की मद्रास उच्च न्यायालय के डब्ल्यू.पी. संख्या 17133 में दिनांक 09.08.2019 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2024 की दीवानी अपील संख्या 6512

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

एस. नंदकुमार, बसंत आर, वरिष्ठ अधिवक्तागण, सुश्री दीपिका नंदकुमार, नरेश कुमार, के.के. मणि, वी.एम. शिवकुमार, सुश्री टी. अर्चना, रौनक अरोड़ा, राजीव गुप्ता, एस. जनार्दनन, डी. कुमानन, सुश्री जी. इंदिरा, अश्विनी कुमार, पी. गंडेपन, सुश्री डी. पूर्णिमा, अधिवक्तागण उपस्थित पक्षकारों के लिए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय / आदेश

निर्णय

संजय करोल, न्यायमूर्ति

1. विशेष अनुमति द्वारा अपील की अनुमति प्रदान की गई।

अपीलें

2. प्रति-अपीलें, एक तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड[1] द्वारा और दूसरी तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन एम्प्लॉइज वेलफेयर यूनियन[2] द्वारा, मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यूपी संख्या 17133/2001 और 15241/2009 में पारित क्रमशः दिनांक 9 अगस्त, 2019 के निर्णय और आदेश को प्रश्नगत करती हैं। पक्षकारों की स्थिति विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 30005/2019 के अनुसार है।

3. आक्षेपित निर्णय निर्दिष्ट आदेश याचिका संख्या 17133/2001 में पारित किया गया था जो श्रम निरीक्षक, सर्कल-III, चेन्नई[3] के दिनांक 31 मार्च, 2001 के आदेश के खिलाफ निर्देशित था, जिसके द्वारा निगम में स्थायी दर्जा दिए जाने के 53 कामगारों के दावे को स्वीकार किया गया था, जबकि 42 अन्य के दावे को खारिज कर दिया गया था।

4. डब्ल्यूपी संख्या 15241/2009 उक्त 53 कामगारों में से 22 द्वारा दायर की गई थी, जिसमें श्रम निरीक्षक के आदेश के अनुसार निगम में रोजगार प्रदान करने के लिए परमादेश रिट की मांग की गई थी।

इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न

5. जिन प्रश्नों पर इस न्यायालय को विचार करना है वे हैं –

(i) क्या तमिलनाडु औद्योगिक प्रतिष्ठान (कामगारों को स्थायी दर्जा प्रदान करना) अधिनियम, 1981 पक्षकारों पर लागू होगा?

---

1 इसके बाद 'निगम'

2 इसके बाद 'संघ' कहा जाएगा

3 इसके बाद इसे 'श्रम निरीक्षक' कहा जाएगा।

(ii) क्या आक्षेपित निर्णय के माध्यम से, गैर-रोजगार पर सवाल उठाने वाले 'औद्योगिक विवाद दावा' को शुरू करने का सुझाव संधारणीय था, यह देखते हुए कि श्रम निरीक्षक ने पहले ही इस संबंध में आदेश पारित कर दिए थे?

संक्षेप में तथ्य

6. निगम को 1 जुलाई, 1994 को भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित किया गया था। इसका प्रबंधन तमिलनाडु राज्य के अधीन है। इसने विभिन्न क्षमताओं में विभिन्न कामगारों को नियुक्त किया है, जिसमें 2020 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 2649 से उत्पन्न अपील में अपीलकर्ता भी शामिल हैं। ऐसे कर्मचारियों ने तमिलनाडु औद्योगिक प्रतिष्ठान (कामगारों को स्थायी दर्जा प्रदान करना) अधिनियम, 1981[4] के प्रावधानों के तहत नियमितीकरण की मांग की थी। इस तरह के अभ्यावेदन असफल होने पर, विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दो निर्दिष्ट आदेश याचिकाएँ संख्या 17263 और 17147/1998 दायर की गई थीं।

7. विद्वान एकल न्यायाधीश[5] ने दिनांक 21 जुलाई, 2000 के निर्णय और आदेश द्वारा निम्नलिखित निर्देश पारित किए:

"19....

1. <u>तमिलनाडु औद्योगिक प्रतिष्ठान (कामगारों को स्थायी दर्जा प्रदान करना) अधिनियम, 1981 (1981 का तमिलनाडु अधिनियम 46) दूसरे उत्तरदाता निगम पर लागू होता है।</u>

---

4 इसके बाद इसे 'अधिनियम' कहा जाएगा।

5 अनुलग्नक पी1, पृष्ठ 61

2. दूसरे उत्तरदाता पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले 'निरीक्षक' को दूसरे उत्तरदाता निगम के अभिलेखों का निरीक्षण और सत्यापन करने और याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों द्वारा किए गए दावे के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है;

3. 'निरीक्षक' को याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों को शनिवार को रोजगार के संबंध में याचिकाकर्ता संघ द्वारा किए गए दावे पर विचार करने का भी निर्देश दिया जाता है;

4. 'निरीक्षक' को दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद इस आदेश की प्रतिलिपि की तारीख से तीन महीने के भीतर ऊपर संदर्भित प्रश्नों को निर्धारित करने का निर्देश दिया जाता है; और

5. जब तक 'निरीक्षक' द्वारा जैसा कि ऊपर बताया गया है, आदेश पारित नहीं किया जाता है, तब तक दोनों पक्षों द्वारा आज की स्थिति के अनुसार यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। निर्दिष्ट आदेश याचिकाओं को ऊपर वर्णित सीमा तक अनुमति दी जाती है। कोई लागत नहीं। सभी विविध याचिकाओं को बंद किया जाता है।"

8. उपरोक्त आदेश के अनुसरण में, श्रम निरीक्षक ने दिनांक 31 मार्च, 2001[6] का आदेश पारित किया, जिसमें निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए:

"मुद्दे

6 अनुलग्नक पी3, पृ.98.

(ए) क्या कामगारों को स्थायी दर्जा प्रदान करने से संबंधित अधिनियम को उत्तरदाता प्रतिष्ठान पर लागू किया जा सकता है?

(बी) क्या उपरोक्त अधिनियम के तहत अधिकृत कार्यालय, श्रम निरीक्षक होने के नाते, इस मामले की सुनवाई करने का अधिकार रखता है?

(सी) यदि, उत्तरदाता का प्रबंधन उपरोक्त अधिनियम के क्षेत्राधिकार में आता है, तो याचिकाकर्ताओं को किस प्रकार की राहत दी जा सकती है?"

9. श्रम निरीक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि जी. सुमति और 52 अन्य कामगार 24 महीने की अवधि में लगातार 480 दिनों तक निगम की सेवा में थे और तदनुसार उन्हें स्थायी दर्जा दिया जा सकता है।

10. यह इस आदेश के खिलाफ है कि हमारे समक्ष आक्षेपित निर्णय और आदेश अंततः पारित किया गया। 21 जुलाई, 2000 के आदेश पर हमला करते हुए एक अपील और श्रम निरीक्षक के दिनांक 31 मार्च, 2001 के आदेश के खिलाफ एक स्वतंत्र निर्दिष्ट आदेश याचिका दायर की गई, और खंडपीठ ने दिनांक 10 दिसंबर 2009[7] के आदेश द्वारा ऐसी कार्यवाही में, इन दोनों आदेशों की पुष्टि की और निगम को उत्तरदाताओं को रोजगार प्रदान करने का निर्देश दिया, जैसे कि वे जो उन कार्यवाहियों में याचिकाकर्ताओं (मूल निर्दिष्ट आदेश याचिकाकर्ता) के रूप में न्यायालय के समक्ष थे। श्रम निरीक्षक के आदेश की ऐसी पुष्टि के खिलाफ, 2012 की दीवानी अपील संख्या 6567 और 6568 को प्राथमिकता दी गई।

11. अतः, इस न्यायालय ने 29 मार्च 2010 को सूचना पत्र जारी करते हुए आक्षेपित निर्णय के संचालन पर रोक लगा दी। इसके बाद, 10 मार्च, 2016 को, अपील की अनुमति देते हुए, इस न्यायालय ने मामले को उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया, इस प्रकार-

---

7 कागज़ की किताब का पृष्ठ 205.

"3. यह प्रस्तुत किया गया है कि निर्दिष्ट आदेश याचिकाओं और संबंधित मामलों का निर्णय करते समय, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि क्या उपरोक्त अधिनियम उत्तरदाता-संघ के सदस्यों पर लागू होता है और उक्त प्रस्तुति सही प्रतीत होती है।

4. पूर्व-कथित परिस्थितियों में, आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है और मामलों को विधि के अनुसार नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। हमें यकीन है कि उच्च न्यायालय मामलों को नए सिरे से सुनेगा और विधि के अनुसार उसका निर्णय करेगा।

5. इस न्यायालय द्वारा दिया गया दिनांक 29 मार्च, 2010 का अंतरिम आदेश तब तक जारी रहेगा जब तक कि उच्च न्यायालय संबंधित पक्षों को सुनने के बाद उसे संशोधित नहीं करता..."

आक्षेपित निर्णय

इस मोड़ पर, यह स्पष्ट करना उचित है कि वर्ष 2000 की निर्दिष्ट आदेश अपील संख्या 1430 और 1431 की खारिजी को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी और जिसे चुनौती दी गई थी वह डब्ल्यूपी संख्या 17133/2001 की खारिजी और डब्ल्यूपी संख्या 15241/2009 में निर्देश थे, जो 2012 की दीवानी अपील संख्या 6567 और 6568 में गए, जिसमें न्यायालय ने मामले को प्रतिप्रेषित कर दिया।

12. प्रतिप्रेषण के उक्त आदेश के अनुसरण में, उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में, विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय के साथ अपनी सहमति दर्ज की, जिसे ऊपर पुनरुत्पादित किया गया है। यह देखा गया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने निगम के प्रबंधन के गठन, इसके द्वारा संचालित गतिविधियों की प्रकृति, आदि की व्यापक रूप से जांच की थी और फिर

निष्कर्ष निकाला कि अधिनियम इस आधार पर लागू होगा कि यह अधिनियम की धारा 2(3)(ई) के तहत एक औद्योगिक प्रतिष्ठान था, और यह कि वे (विद्वान खंडपीठ) उसी के साथ सहमत हैं।

13. यह आगे देखा गया कि चूंकि विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ निर्दिष्ट आदेश अपीलें खारिज होने के बाद कोई अपील दायर नहीं की गई थी, इसलिए श्रम निरीक्षक का आदेश अंतिम हो गया था। निगम पर अधिनियम के लागू होने के संबंध में स्वतंत्र विश्लेषण पर, यह निम्नानुसार देखा गया:

> "50. हालांकि तथ्यों के स्वतंत्र विश्लेषण पर, हम स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित करते हैं कि 1981 के तमिलनाडु अधिनियम, 46 के प्रावधान टीएनएमएससी प्रबंधन पर लागू होते हैं, इस तथ्य को देखते हुए कि, टीएनएमएससी प्रबंधन अधिनियम की धारा 2(3)(ई) के तहत परिभाषित एक औद्योगिक प्रतिष्ठान है और यह 1947 के तमिलनाडु अधिनियम, 36 की धारा 2(6) के तहत परिभाषित एक प्रतिष्ठान है। उपरोक्त तर्क से हम निर्णायक रूप से अभिनिर्धारित करते हैं कि टीएनएमएससी प्रबंधन एक औद्योगिक प्रतिष्ठान है और 1981 के तमिलनाडु अधिनियम, 46 के प्रावधानों के अंतर्गत आता है।"

पक्षकारों की दलीलें

14. हमने पक्षकारों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना है और लिखित प्रस्तुति का अवलोकन किया है। अपीलकर्ता की ओर से, यह प्रस्तुत किया गया है :-

क) कि इस न्यायालय के दिनांक 10 मार्च, 2016 के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। अपीलकर्ता की विशिष्ट दलील कि अधिनियम, साथ ही तमिलनाडु

दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1947[8] अपीलकर्ता पर लागू नहीं होगा। हालाँकि, उच्च न्यायालय द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया। एकमात्र तरीका जिससे उक्त अधिनियम लागू हो सकता था वह यह था कि निगम 1947 के अधिनियम की धारा 2(3) के तहत 'वाणिज्यिक प्रतिष्ठान' की परिभाषा के अंतर्गत आएगा।

ख) कि आक्षेपित निर्णय में यह विश्लेषण नहीं किया गया कि क्या निगम की कोई भी गतिविधि 1947 के अधिनियम की धारा 2(3) के अंतर्गत आती है। अधिनियम की धारा 7 ऐसे उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों को छूट देती है, जो निर्माण गतिविधियों में लगे हुए हैं और चूंकि निगम की कुछ गतिविधियों में निर्माण शामिल है, इसलिए निगम को छूट दी जाएगी।

ग) कि 53 कर्मचारियों में से अधिकांश जो 2020 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 2649 से उत्पन्न अपील में अपीलकर्ता हैं, जिन्हें श्रम निरीक्षक द्वारा स्थायी दर्जा दिए जाने का निर्देश दिया गया था, ने अन्य लाभकारी रोजगार प्राप्त कर लिया है और निगम को स्थायी दर्जा देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

15. उत्तरदाता-संघ (यूनियन) ने प्रस्तुत किया है -

(क) कि निगम अस्थायी कर्मचारियों के रूप में वर्षों तक उनका शोषण करने के बाद **कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी**[9] के अनुपात को लागू करके उत्तरदाताओं की स्थिति में अंतर करने का प्रयास कर रहा है। **महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन**

8 इसके बाद 1947 अधिनियम.

9 [2006] 3 एससीआर 953 : (2006) 4 एससीसी 1

निगम बनाम कास्ट्राईब राज्य परिवहन कर्मचारी संगठन[10] और विशेष रूप से, उसके कंडिका 32 से 36 पर अवलंबन किया गया है।

(ख) **यू.पी. पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और एक अन्य बनाम बिजली मजदूर संघ और अन्य**[11] पर भरोसा करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि औद्योगिक न्यायनिर्णायक, हालांकि रोजगार की शर्तों को बदल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता हो और यदि मौजूदा मामला नियमितीकरण की अवधारणा द्वारा आच्छादित किया गया है, तो वही नियम लागू होता है।

(ग) **ओएनजीसी लिमिटेड बनाम पेट्रोलियम कोल लेबर यूनियन और अन्य**[12] और **अजय पाल सिंह बनाम हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन**[13] पर अवलंबन करते हुए, यह आग्रह किया गया है कि **उमा देवी** (उपरोक्त) में औद्योगिक और श्रम न्यायालयों की शक्तियों पर विचार नहीं किया गया था।

(घ) 2020 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 2649 से उत्पन्न अपील में 12 अपीलकर्ताओं के संबंध में एक सारणीबद्ध चार्ट प्रदान किया गया है और यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि श्रम निरीक्षक ने अपने आदेश के माध्यम से उक्त कामगारों को स्थायी दर्जा प्रदान करने की पात्रता घोषित कर दी है, इसलिए गैर-रोजगार पर सवाल उठाते हुए औद्योगिक विवाद उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे उत्तरदाता जो सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच गए हैं,

---

10 [2009] 13 एससीआर 937 : (2009) 8 एससीसी 556

11 [2007] 5 एससीआर 256 : (2007) 5 एससीसी 755

12 [2015] 5 एससीआर 474 : (2015) 6 एससीसी 494

13 (2015) 6 एससीसी 321

वे **रणबीर सिंह बनाम एस.के. रॉय, अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम और एक अन्य**[14] में मान्यता प्राप्त नियमितीकरण के बदले मुआवजे के हकदार होंगे।

विश्लेषण और विचार

16. वर्तमान विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए प्रासंगिक प्रावधान संदर्भ की आसानी के लिए नीचे पुनरुत्पादित किए गए हैं :-

2. परिभाषाएँ - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो,-

x x x x x

(3)"औद्योगिक प्रतिष्ठान" का अर्थ है-

(ए).....; या

(बी).....; या

(सी).....; या

(डी).....; या

(ई) तमिलनाडु दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1947 (1947 का तमिलनाडु अधिनियम XXXVI) की धारा के खंड (6) में परिभाषित एक प्रतिष्ठान; या

(एफ).....; या

14 [2022] 10 एससीआर 986 : 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 521

(जी) कोई अन्य प्रतिष्ठान जिसे सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक औद्योगिक प्रतिष्ठान घोषित कर सकती है।

(4) "*कामगार*', का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में किसी भी कुशल या अकुशल, मैनुअल पर्यवेक्षी, तकनीकी या लिपिकीय कार्य को करने के लिए किराए या इनाम के लिए नियोजित है, चाहे रोजगार की शर्तें अभिव्यक्त या विवक्षित हों [और इसमें बदली कामगार शामिल है, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं है,-

(ए) जो पुलिस सेवा में या जेल के अधिकारी या अन्य कर्मचारी के रूप में नियोजित है; या

(बी) जो मुख्य रूप से प्रबंधकीय या प्रशासनिक क्षमता में नियोजित है; या

(सी) जो, पर्यवेक्षी क्षमता में नियोजित होने के नाते, [प्रति माह तीन हजार पांच सौ रुपये से अधिक वेतन लेता है] या कार्यालय से जुड़े कर्तव्यों की प्रकृति या उसमें निहित शक्तियों के कारण, मुख्य रूप से प्रबंधकीय प्रकृति के कार्यों का प्रयोग करता है।

x x x x x

3. कामगारों को स्थायी दर्जा प्रदान करना। - (1) उस समय लागू किसी भी कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, <u>हर कामगार जो एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में चौबीस कैलेंडर महीनों की अवधि में चार सौ अस्सी दिनों की अवधि के लिए निरंतर सेवा में है, उसे स्थायी किया जाएगा।</u>

(2) एक कामगार को एक अवधि के लिए निरंतर सेवा में कहा जाएगा यदि वह, उस अवधि के लिए, निर्बाध सेवा में है, जिसमें वह सेवा भी शामिल है जो बीमारी या अधिकृत अवकाश या दुर्घटना या हड़ताल, जो अवैध नहीं है, या तालाबंदी [xxx], या काम की समाप्ति जो कामगार की ओर से किसी भी गलती के कारण नहीं है, के कारण बाधित हो सकती है।

स्पष्टीकरण [I] - [उप-धाराओं (1) और (2) में संदर्भित निरंतर सेवा की गणना के प्रयोजनों के लिए, एक कामगार को उन दिनों के दौरान निरंतर सेवा में माना जाएगा जिन दिनों] -

(i) उसे एक समझौते के तहत या औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का केंद्रीय अधिनियम XX) के तहत बनाए गए स्थायी आदेशों द्वारा या औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू किसी अन्य कानून के तहत काम से हटा दिया गया है;

(ii) वह पूर्ण वेतन के साथ अवकाश पर रहा है, जो इस रोजगार के दौरान अर्जित किया गया है; और

(iv) एक महिला के मामले में, वह मातृत्व अवकाश पर रही है; हालांकि, इस प्रकार कि ऐसे मातृत्व अवकाश की कुल अवधि बारह सप्ताह से अधिक न हो।

[स्पष्टीकरण II। - इस धारा के प्रयोजन के लिए, कानून' में कोई भी पंचाट, समझौता, बंदोबस्त, विलेख या सेवा का अनुबंध शामिल है, चाहे वह इस अधिनियम के शुरू होने से पहले या बाद में किया गया हो।]"

(जोर दिया गया)

17. यहाँ मुख्य मुद्दा कर्मचारियों और उनके संघ के संबंध में निगम पर अधिनियम का लागू होना है। इसकी जांच करने के लिए, जिस पर विचार किया जाना है वह यह है कि क्या ऊपर पुनरुत्पादित प्रावधानों के अनुसार निगम को एक औद्योगिक प्रतिष्ठान कहा जा सकता है

और क्या संघ के सदस्य कामगार के रूप में अर्हता प्राप्त करेंगे और इसलिए अधिनियम की धारा 3 के तहत स्थायी स्थिति के लिए पात्र होंगे।

18. उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर धारा 2(3)(ई), जैसा कि ऊपर है, यानी 1947 के अधिनियम की धारा 2(6) के तहत प्रदान की गई 'प्रतिष्ठान' की परिभाषा के अनुरूप विचार किया। यह इस प्रकार है -

> "2. परिभाषाएँ- इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो-
>
> x x x x x
>
> (6) 'प्रतिष्ठान' का अर्थ है एक दुकान, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, रेस्तरां, भोजनालय, आवासीय होटल, थिएटर या सार्वजनिक मनोरंजन या आमोद-प्रमोद का कोई भी स्थान और इसमें ऐसा प्रतिष्ठान शामिल है जिसे 1 [राज्य] सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक प्रतिष्ठान घोषित कर सकती है;"

19. किसी प्रतिष्ठान को 1947 के अधिनियम के तहत परिभाषा के अंतर्गत आच्छादित करने के लिए, जब तक कि वह विशेष रूप से उल्लिखित में से एक न हो, उसे धारा 2(3) के तहत परिभाषित एक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान होने की शर्त को पूरा करना होगा जो इस प्रकार है -

> "(3) 'वाणिज्यिक प्रतिष्ठान' का अर्थ है एक ऐसा प्रतिष्ठान जो दुकान नहीं है, लेकिन जो विज्ञापन, कमीशन, अग्रेषण या वाणिज्यिक एजेंसी का व्यवसाय करता है, या जो किसी कारखाने या औद्योगिक उपक्रम का लिपिकीय विभाग है या जो एक बीमा कंपनी, संयुक्त स्टॉक कंपनी, बैंक, दलाल का कार्यालय या एक्सचेंज है और इसमें ऐसे अन्य प्रतिष्ठान शामिल हैं जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वाणिज्यिक प्रतिष्ठान घोषित कर सकती है।"

20. उच्च न्यायालय के समक्ष निगम द्वारा दायर 16 सितंबर, 2009 का शपथपत्र यह दर्ज करता है कि वर्ष 2007-2008 के लिए वास्तविक कारोबार 27.5 करोड़ रुपये है, जबकि वितरित दवाओं का मूल्य 186.60 करोड़ रुपये है। श्रम निरीक्षक का आदेश इस प्रकार दर्ज करता है -

> "आगे उत्तरदाता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन किसी लाभ के उद्देश्य से कार्य नहीं कर रहा है, कि गुणवत्ता वाली दवाएं गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण से प्राप्त की जा रही हैं और उन्हें बिना किसी सेवा शुल्क के उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जा रही है और इसलिए, उत्तरदाता का प्रतिष्ठान किसी भी वाणिज्यिक कर्तव्य में शामिल नहीं है और उपरोक्त सभी कारकों और याचिकाकर्ता की ओर से दायर उत्तरदाताओं के लेखा परीक्षित बैलेंस शीट यानी वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के लिए अवलोकन करते समय, यह देखा गया है कि वर्ष 1994-95 के लिए 6.96 लाख रुपये और 1995-96 के लिए 8.44 लाख रुपये और 1996-97 के लिए 1.84 लाख रुपये का लाभ प्राप्त हुआ था। इसलिए यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि उत्तरदाता के प्रतिष्ठान का कोई लाभ का इरादा नहीं है जैसा कि उत्तरदाता द्वारा उल्लेख किया गया है, बिल्कुल भी सत्य नहीं है।"

21. किसी भी प्रतिष्ठान के वाणिज्यिक होने के लिए, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि उसके द्वारा की जाने वाली गतिविधियां कुछ मौद्रिक लाभ कमाने के लिए हैं। सबसे बुनियादी अर्थों में वाणिज्यिक का अर्थ है पैसे के बदले माल खरीदना या बेचना। जैसा कि ऊपर पुनरुत्पादित, निर्विवाद कंडिका (उच्च न्यायालय द्वारा भी दर्ज किया गया) स्थापित करता है, वाणिज्यिक तत्व अनुपस्थित नहीं था।

22. इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था कि निगम द्वारा संचालित गतिविधियां 1947 के अधिनियम की धारा 2(3) के तहत उल्लिखित गतिविधियों के अंतर्गत नहीं आती हैं। इस प्रस्तुति को स्वीकार करना भी मुश्किल है। निर्माण कार्य, जिसे निगम, अपनी स्वयं की

स्वीकृति से, करता है, गैर-सरकारी निकायों जैसे कि फर्मों, कंपनियों और व्यक्तियों के लिए भी है। इस संबंध में उच्च न्यायालय की टिप्पणियों, विशेष रूप से आक्षेपित निर्णय के कंडिका 37 और 38 को संदर्भित करना उचित होगा, जिन्हें संदर्भ की आसानी के लिए नीचे पुनरुत्पादित किया गया है:

"37. टीएनएमएससी प्रबंधन भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है जो पूरी तरह से तमिलनाडु सरकार के स्वामित्व में है। कंपनी के उद्देश्य जैसा कि एसोसिएशन के लेखों का ज्ञापन से देखा

गया है, वे इस प्रकार हैं:

"(i) सभी प्रकार और किस्मों की जेनेरिक और पेटेंट दवाएं, ड्रग्स, मिश्रण, फॉर्मूलेशन, टैबलेट, गोलियां, पाउडर, औषधि विज्ञान और चिकित्सा उत्पाद, सुई, सीरिंज, इंजेक्शन, टीके, सीरा, इम्यूनोजेन्स, फाइलाकोजेन्स, रसायन और सर्जिकल ड्रेसिंग, किट और उपकरण खरीदना या अन्यथा प्राप्त करना और विभिन्न अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों को बेचना या आपूर्ति करना।

(ii) अस्पतालों में आवश्यक सभी प्रकार के पूंजीगत उपकरणों और उपकरणों को खरीदना, वितरित करना, इकट्ठा करना, स्थापित करना, बनाए रखना या अन्यथा सौदा करना।

(iii) सरकार के लिए, या स्थानीय प्राधिकरणों, निगमों, सोसायटियों, न्यासों, कंपनियों, फर्मों और व्यक्तियों सहित किसी अन्य व्यक्ति के लिए अस्पतालों और या अन्य भवनों के डिजाइन और निर्माण का कार्य करना।

(iv) विभिन्न चिकित्सा उपकरणों, सर्जिकल उपकरणों, नैदानिक उपकरणों, अग्निशमन उपकरणों, फर्नीचर और - अस्पताल के फर्नीचर सहित फिटिंग के निर्माण, संयोजन, मरम्मत या अन्यथा बनाए रखने के लिए आधुनिक गोदाम

और इंजीनियरिंग कार्यशालाएं स्थापित करना और अस्पतालों के नागरिक और अन्य सामान्य रखरखाव का कार्य भी करना।

(v) विभिन्न तकनीकी-प्रबंधकीय क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए चिकित्सा और पैरा-मेडिकल कर्मियों के लिए अनुसंधान और विकास केंद्र और संस्थान स्थापित करना।"

(जोर दिया गया)

38. यह भी देखा गया है कि टीएनएमएससी प्रबंधन के चैनल में और सभी जिला मुख्यालयों में गोदाम हैं। इन गोदामों का उपयोग दवाओं और ड्रग्स के भंडारण के लिए किया जाता है। श्रम निरीक्षक द्वारा 31.03.2001 के आदेश में एक तथ्य के रूप में यह विशेष रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि टीएनएमएससी प्रबंधन ने वर्ष 1994-95 में 6.95 लाख रुपये, वर्ष 1995-96 में 8.44 लाख रुपये और वर्ष 1996-97 में 1.84 लाख रुपये का लाभ कमाया था। परिणामस्वरूप, कोई भी विवाद जो यह उठाया गया है कि इसे "बिना लाभ के आधार" पर चलाया जा रहा है, उसे खारिज किया जाना चाहिए।"

23. यह तर्क दिया गया था कि निगम की गतिविधियों में निर्माण शामिल है और इसलिए इसे अधिनियम के आवेदन से छूट दी जाएगी। धारा 7 इस प्रकार है-

"7. अधिनियम का कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कामगारों पर लागू न होना। - इस अधिनियम में निहित कोई भी बात भवनों, पुलों, सड़कों, नहरों, बांधों या अन्य निर्माण कार्यों, चाहे वह संरचनात्मक, यांत्रिक या विद्युत हो, के निर्माण में लगे औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत कामगारों पर लागू नहीं होगी।"

प्रावधान की भाषा स्पष्ट है। इसका तात्पर्य यह है कि यह अधिनियम उन कामगारों पर लागू नहीं होगा जो भवनों और इसी तरह के निर्माण या अन्य निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, चाहे वह संरचनात्मक, यांत्रिक या विद्युत हो। इसलिए, वे प्रतिष्ठान और उनके कामगार छूट प्राप्त

करेंगे, जो विशेष रूप से निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। निगम के उद्देश्य, जिन्हें उच्च न्यायालय के समक्ष संघ के शपथपत्र में पुनरुत्पादित किया गया है, बताते हैं:-

"

x x

x

iii) सरकार, या स्थानीय प्राधिकरणों, निगमों, सोसायटियों, न्यासों, कंपनियों, फर्मों और व्यक्तियों सहित किसी अन्य व्यक्ति के लिए अस्पतालों और अन्य भवनों के डिजाइन और निर्माण का कार्य करना।

..."

24. हालाँकि, हमारी राय में, यह निगम को अधिनियम के तहत जिम्मेदारियों या दायित्वों से अपना पल्ला झाड़ने की अनुमति नहीं देगा, क्योंकि निगम द्वारा किया जाने वाला निर्माण, इसके द्वारा की जाने वाली कई गतिविधियों में से केवल एक है। सभी श्रमिकों को अधिनियम के दायरे से बाहर करना, विशेष रूप से, जब उक्त श्रमिक, उत्तरदाता संघ के सदस्यों की तरह, निर्माण कार्य करने वाले नहीं थे, अनुचित है।

25. आगे यह तर्क दिया गया था कि श्रम निरीक्षक के आदेश द्वारा स्थायी रोजगार प्रदान करने के लिए निर्देशित कई व्यक्तियों को कहीं और लाभकारी रोजगार मिल गया है, और इसलिए उनकी ओर से विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हम इस प्रस्तुति को स्वीकार नहीं कर सकते। केवल इसलिए कि रोजगार विवाद में शामिल कुछ व्यक्तियों को कथित तौर पर अन्य रोजगार मिल गया है, यह दूसरों के दावों को खारिज करने को उचित नहीं ठहराता है। 2020 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 2649 से उत्पन्न अपील में अपीलकर्ताओं की लिखित प्रस्तुतियों के अनुसार, बारह अपीलकर्ताओं ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। और इसलिए, इसे इसके तार्किक निष्कर्ष तक देखा जाना चाहिए।

26. अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि उत्तरदाता एक निश्चित समय के बाद सेवा में बने नहीं रहे, हालांकि, उक्त तर्क को स्वीकार नहीं किया गया था और हमें तथ्य पर एक अलग दृष्टिकोण लेने का कोई कारण नहीं मिलता है जो वर्ष 1997 से साबित और न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त है।

27. इस प्रकार, दोनों आवश्यकताएं, प्रतिष्ठान के प्रदान किए गए अनुसार औद्योगिक प्रतिष्ठान की परिभाषा के अंतर्गत आने की और कर्मचारी के 24 महीनों के लिए 480 दिनों या उससे अधिक समय तक सेवा में निर्बाध रूप से बने रहने की, पूरी होने पर, हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि अधिनियम वर्तमान विवाद के पक्षकारों पर लागू होगा।

28. विचार किया जाने वाला अगला प्रश्न यह है कि क्या प्रतिप्रेषण पर उच्च न्यायालय, श्रम निरीक्षक के आदेश की अनदेखी कर सकता था और सुझाव दे सकता था कि कर्मचारी अपने गैर-रोजगार पर सवाल उठाते हुए एक औद्योगिक विवाद उठाएं। प्रतिप्रेषण का कारण, जैसा कि 10 मार्च, 2016 के निर्णय से देखा गया है, यह था कि उच्च न्यायालय ने इस पर विचार नहीं किया था कि अधिनियम पक्षकारों पर लागू होगा, जो हमारे सामने पक्षकारों के समान ही थे। दूसरे शब्दों में, प्रतिप्रेषण का दायरा सीमित था। श्रम निरीक्षक का आदेश अधिनियम के तहत पारित किया गया था। चूंकि उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अधिनियम लागू होगा, इसलिए श्रम निरीक्षक के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था और, इसलिए, उसे केवल यह आदेश देना चाहिए था कि श्रम निरीक्षक का आदेश, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया था कि उत्तरदाता-संघ के सदस्यों को स्थायी रोजगार दिया जाए, का अनुपालन किया जाए। जब कोई मुद्दा पहले से ही तय हो चुका है और ऐसा निर्णय अधिकार या क्षेत्राधिकार के किसी भी दोष से ग्रस्त नहीं है, तो उन लोगों को जिनके पक्ष में आदेश है, उन्हें एक बार फिर से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत प्राधिकरण के

समक्ष अपने दावे को फिर से स्थापित करने की प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर करना, अनुचित होगा।

29. निगम द्वारा दायर अपील (2019 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 30005 से उत्पन्न अपील) को, उपरोक्त के संदर्भ में, खारिज किया जाता है और उत्तरदाता-संघ द्वारा उसके अध्यक्ष, जी. सुमति के माध्यम से दायर अपील (2020 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 2649 से उत्पन्न अपील) को तदनुसार कानून के तहत उत्तरदाता-कर्मचारियों के पक्ष में सभी परिणामों का पालन करने के लिए अनुमति दी जाती है।

लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निस्तारित माने जाएंगे।

मामले का परिणाम: निगम द्वारा दायर अपील खारिज।

संघ द्वारा दायर अपील स्वीकार।

निर्णय सार लेखन : निधि जैन

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।